भारत की जनता को आह्वान !

सामंतवादी और साम्राज्यवादी बेड़ियों को तोड़ो!

इस सड़ी-गली व्यवस्था को उखाड़ फेंको!

खुद अपने हाथों से अपने और देश के भविष्य का निर्माण करो!

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

भारत की जनता को आह्वान !

सामंतवादी और साम्राज्यवादी बेड़ियों को तोड़ो!

इस सड़ी-गली व्यवस्था को उखाड़ फेंको!

खुद अपने हाथों से अपने और देश के भविष्य का निर्माण करो!

प्यारे लोगों,

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की तरफ से पार्टी की दसवीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर हम आपको हार्दिक अभिवादन पेश करते हैं।

दस साल पहले, एक खुशी की घोषणा करने के लिए हम आपके सामने आये थे – और वह अवसर था दो क्रान्तिकारी धाराओं का विलय। क्रान्ति के कार्यभारों को कंधे पर लेने के लिए 21 सितम्बर 2014 को एक एकीकृत माओवादी पार्टी के रूप में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की स्थापना हुई थी। यहां हम आपके सामने इन दस महत्वपूर्ण सालों का एक लेखा-जोखा पेश कर रहे हैं। यह दशक देश के सर्वश्रेष्ठ बेटियों और बेटों के साहसिक संघर्षों और वीरतापूर्ण शहादतों का रहा है। दण्डकारण्य (छत्तीसगढ़), बिहार, झारखंड, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओड़िशा, पश्चिम बंग, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम में इस दौरान दो हजार पांच सौ साथियों ने अपने बहुमूल्य प्राणों की कुरबानी दी। इनमें शामिल हैं पार्टी के सर्वोच्च स्तर से लेकर बुनियादी स्तर के सैकड़ों महान नेता। शोषकों के किराये के बलों से बहादुरी के साथ लड़ते हुए जनमुक्ति छापामार सेना (पीएलजीए) के कई वीर योद्धाओं ने लड़ाई में अपना खून बहाया। जनता में से भी बहुतों ने सर्वोच्च कुरबानी दी।

यह खून व्यर्थ नहीं बहाया गया। पिछली उपलब्धियों और कीमती अनुभवों को इसने और ज्यादा सुदृढ़ किया। राजनीतिक, सैनिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक क्षेत्रों में इसने एक दशक तक दृढ़तापूर्ण संघर्ष के इंधन का काम किया। जनता पर सदियों से हावी शोषण और उत्पीड़न को खत्म करने के लिए लाखों की

तादाद में जनता, खासकर समाज के सबसे निचले पायदान की जनता इस दौरान व्यापक जुझारू जनविद्रोहों में गोलबंद हुई । इन गौरवशाली वर्षों में पुरानी सत्ता को ध्वस्त कर प्राथमिक स्तर पर नये समाज की और व्यापक स्तर पर निर्माण करते हुए नई राजनीतिक सत्ता की अंकुर का पालन-पोषण किया गया। इस प्रक्रिया में, पीएलजीए की लड़ाकू क्षमता और संख्या को और मजबूत किया गया। इसकी बुनियादी बल (बेस फोर्स) जन मिलिशिया अब हजारों की संख्या में है। ये बहादुर महिला और पुरूष जनता की सभी उपलब्धियों - राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, और खासकर, उसके द्वारा निर्मित किये जा रहे नये समाज - की सुरक्षा के लिए हाथों में हथियार लेकर खड़े हैं।

हां, हमने आप से पहले जो वादे किए थे उन्हे पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश की और कुछ उपलब्धियां हासिल की। यह इसलिए क्योंकि हम कम्युनिस्ट हैं। हमारी कथनी का प्रमाण व्यवहार में, जनता की सेवा में, है। देशी और विदेशी शोषकों के खिलाफ इस मिट्टी की जनता के द्वारा सदियों से किए जा रहे अनगिनत विद्रोहों की महान पराम्परा को विरासत में लेते हुए, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ, देश की असली आजादी के लिए देशभक्तों के वीरतापूर्ण संघर्षों की लंबी श्रंखला से प्रेरणा लेते हुए, तेलंगाना सशस्त्र क्रान्तिकारी संघर्ष, तेभागा और पुन्नप्रा-वयालार के लाल योद्धाओं से विरासत में मिले हथियारबंद संघर्ष के परचम को दृढ़ता से ऊंचा उठाकर, दुनिया के लाखों शहीदों के खून से सने लाल झंडे को हमेशा ऊंचा उठाकर हम लड़ते जायेंगे - जब तक हम अपने प्यारे देश को साम्राज्यवाद और उसके दलालों के शिकंजे से मुक्त नहीं कर लेते, इसे विश्व समाजवादी क्रान्ति का आधार नहीं बना लेते और समाजवाद से होते हुए साम्यवाद के उज्वल भविष्य तक अपना रास्ता तय नहीं कर लेते। हम अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग के एक दस्ते के रूप में सभी उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं, शोषित जनता और पूंजीवादी देशों की व्यापक जनता के हथियारबंद हमसफर बनकर लड़ते रहेंगे। यह इसलिए, क्योंकि हम है उस महान वसंत वज्रनाद - 1967 के महान नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान विद्रोह - की सन्तान जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। हमारे महान संस्थापक नेता कॉमरेड्स चारू मजूमदार और कन्हाई चटर्जी तथा कई अन्य प्यारे नेताओं ने हमें शिक्षित और प्रशिक्षित किया है। अंतरराष्ट्रीय सर्वहारा का सिद्धान्त - मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद - हमारा मार्गदर्शक है।

प्यारी जनता,

हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। हां, यह सच है कि घृणित औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ। लेकिन हमारी जिंदगी की बिगड़ती हालत इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने पर मजबूर करती है कि विदेशी मालिक सिर्फ पर्दे के पीछे चले गए हैं। सभी महत्वपूर्ण नियंत्रण अभी भी उनके हाथों में ही हैं। उनकी मौजूदगी हम उन बड़े बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में देखते हैं जो हमारे श्रम का शोषण और संसाधनों का लूटपाट करने के लिये आए है; उनके लिए हमारी जिंदगियों की मूल्यहीनता भोपाल गैस कांड जैसे हादसों में देख सकते है। हमारे पूरे देश पर विदेशी शक्तियों के हजारों तरीकों के नियंत्रण में हम उनकी मौजूदगी देख सकते हैं। हम इसे उपभोक्तावाद और आत्मकेन्दित व्यक्तिवाद के प्रोत्साहन में देख सकते हैं। उनकी सड़ी-गली मूल्यों की घुसपैठ और हमारी जीवन शैलियों की भिन्नताओं और संस्कृतियों के प्रति उनकी घृणा में हम अनुभव करते हैं। आईएमएफ, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसे संगठनों के जरिए हमारे ऊपर थोपी गयी विनाशकारी आर्थिक नीतियों की घुटन में महसूस करते हैं - नीतियां जो लोगों को अपनी जड़ों से अलग कर देती हैं, निर्भरता की नयी बेड़ियां तैयार करती हैं और हवा, पानी और जमीन को प्रदूषित करती हैं। सशस्त्र कृषि क्रान्तिकारी युद्ध के खिलाफ छेड़े गए प्रतिक्रान्तिकारी 'जनता पर युद्ध' के लिए भारतीय राज्य को हथियारबंद और प्रशिक्षित करने में इनके घिनौने हाथ देख सकते हैं। यह है साम्राज्यवाद, हमारी पीठ पर सवार तीन बड़े पहाड़ों में से एक।

दो पहाड़ और भी हैं।

देश के शासक हमे कहते हैं कि हम एक्सप्रेस हाईवे, बुलेट ट्रेन, हाई-टेक शहरों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। वे इस तरह की बातें कहते ही जाते हैं। लेकिन अपनी चारों ओर नजर दौड़ाकर देखिए, अपनी जिंदगी को ही देख लीजिए। जरा सोचिए, इन स्मार्ट फोनों, केबल टीवी, मोटरसाईकलों, इलेक्ट्रानिक उपकरणों और चमकीले पहनावों के बावजूद क्यों प्रतिक्रियावादी परम्पराओं के बंधन हमारे ऊपर इतने हावी हैं? अभी भी पुराने और नये जमींदार तथा लालची साहुकार किसानों के फसल का बड़ा हिस्सा क्यों हड़प लेते हैं? क्यों उनकी सोच पत्थर की लकीर बन जाती है? क्यों उनके मुंह से निकली बात कानून बन जाती है, जबकि हमें कहा जाता है कि हम सब बराबर है? क्यों आज भी ज्यादा

से ज्यादा जमीन मुठ्ठीभर लोगों के कब्जे में हैं जबकि बहुसंख्यक आबादी अपना श्रम बेचकर या जमीन के एक टुकड़े पर जिंदगी बसर करने को मजबूर है? महिलाएं क्यों आज भी पुरानी परम्पराओं के बंधनों में बंधी है? दलितों को क्यों अब भी निशाना बनाया जाता है? आदिवासी क्यों आज भी उपेक्षित हैं? अत्याधुनिक अंतरिक्षयानों के प्रक्षेपण के समय भी क्यों हास्यास्पद ब्राह्मणवादी कर्मकांड का ढोंग रचा जाता है? अमानवीय जाति व्यवस्था क्यों आज भी जिंदा और मजबूत है? कई बदलाव आये हैं, कई नई चीजें भी आई हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन सदियों पुरानी सामाजिक ढांचा और मूल्य आज भी जीवित हैं, चाहे वह जातिवाद का हो, पितृसत्ता का हो या फिर हो भूस्वामीवाद का। यह है सामंतवाद, जो जाति से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है और दूसरे बड़े पहाड़ के रूप में हमें दबा रहा है।

हां, शोषक कभी-कभी यह मान भी लेते हैं कि पुराने के अवशेष अब भी मौजूद हैं। लेकिन वे हमारा ध्यान तेजी से बढ़ते शहरों की चकाचौंध, बड़े-बड़े कारखानों और बड़ी कम्पनियों, जिनमें से कुछेक विदेशों में भी अपनी पैठ जमा रही हैं, की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। बहुत खूब, लेकिन क्या आपको असलियत की याद दिलाने की जरूरत है? इन चमचमाते शहरों के अंदर बसे झोपड़-पट्टियों की गंदगी और बदहाली को झेलते हुए क्या आपने वहां जिंदगी नहीं गुजारी है? क्या आप उनकी जमीन के प्रति भूख, संसाधनों की लूट और अंतहीन लालच से पहले से ही परिचित नहीं है जिन्होंने आपको आपके पुरखों की जमीन से बेदखल कर दिया है? क्या आप उनके बेलगाम शोषण से वाकिफ नहीं है; क्या आपके मौलिक अधिकारों के हनन को आपने कभी अनुभव नहीं किया है और इन अधिकारों की मांग करने वालों पर उनके खुंखार हमलों को नहीं देखा है? इतना ही नहीं, बेशक वे बड़े पूंजीपति हैं। लेकिन उनके सभी दिखावों के बावजूद वे विदेशी ताकतों व साम्राज्यावादियों के गुलामों के सिवाय और कुछ नहीं हैं। औपनिवेशिक शासकों के कमिशन-एजेंट के रूप में उपजे ये दलाल हमेशा उनके आकाओं पर अपने अस्तित्व और विकास के हर पहलू के लिए निर्भर रहते हैं। इस निर्भरता पर ही उनका अस्तित्व कायम है। हमारे देश, हमारे देशवासियों और हमारे संसाधनों को वे विदेशी लुटेरों के हाथों नीलाम करते हैं। वे चाहे जितने भी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करते हों, ब्राह्मणवादी सामंती मूल्यों को वे अपने अंदर समेटे रहते हैं। जन्म से ही वे सामंतवाद के साथ जुड़े रहते हैं। वे हैं दलाल नौकरशाह पूंजीपति, नौकरशाह पूंजीवाद के

प्रतिनिधि तथा हमारी पीठ पर सवार और एक बड़ा पहाड़।

हमारे ऊपर हावी ये तीन बड़े पहाड़ हैं। वे हमारी सांस को नियंत्रित करते हैं, हमारा कमर तोड़ देते हैं। वे हमारे देश के विकास और प्रगति को रोकते हैं। हमारे भविष्य को अपने हाथों में लेने के लिए, आजाद होकर खड़े होने के लिए, जनवाद और समानता की खुली हवा में सांस लेने के लिए, हवा-पानी-जमीन को साफ रखने के लिए, समाज को जाति, पितृसत्ता और साम्प्रदायिकतावाद के चंगुल से मुक्त करने के लिए, सभी तरह की प्रतिक्रियावाद के जड़ों में बसे ब्राह्मणवाद को ध्वस्त करने के लिए, और हां, एक मानवीय जीवन जीने के लिए, इन पहाड़ों को हमें उखाड़ फेंकना ही होगा। हम इसी के लिए लड़ते हैं। हमारा लक्ष्य - नई जनवादी क्रान्ति का यही मतलब है। साम्राज्यवादी गुलामी, शोषण और नियंत्रण को उखाड़ कर यह क्रान्ति राष्ट्रीय आजादी स्थापित करेगी तथा सामंतवादी तानाशाही को उखाड़कर जनता के सच्चे लोकतंत्र स्थापित करेगी। मजदूर वर्ग के नेतृत्व में यह क्रान्ति मजदूरों, किसानों, शहरी निम्न पूंजीपति और राष्ट्रीय पूंजीपति का शासन स्थापित करेगी। यह नया जनवादी राज्य राष्ट्रीयताओं के अलग होने के अधिकार सहित उनके आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देगी।

वे कहते है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। देश का संविधान इसे 'समाजवादी' होने का भी दावा करता है! भारत की करोड़ों जनता के साथ, जो हर दिन बीस रूपये में अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हैं, यह एक भद्दा मजाक के अलावा और क्या है? और इसकी धर्मनिरपेक्षता? 1947 के बाद क्या यहां एक भी साल ऐसा गुजरा है जिसमें साम्प्रदायिक हमला न हुआ हों, खासकर मुसलमान अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर? 1984 में कांग्रेस शासन के दौरान सिक्खों और 2002 में भाजपा के शासन में मुसलमानों को हजारों की तादाद में कत्ले-आम को क्या हम भुला सकते हैं? शासक यह दावा करते हैं कि भारत की ताकत इसकी 'भिन्नताओं में एकता' में है। लेकिन इन राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भिन्नताओं के साथ किस तरह का बरताव किया जाता है? अहंकारभरी घृणा, नस्लवादी और जातिवादी अपमान और हमलों के रूप में। यह स्थिति केवल आदिवासियों और दलितों की ही नहीं है। पूर्वोत्तर के राष्ट्रीयताओं के लोगों का भी यही कड़वा अनुभव हैं। कश्मीरी, नागा और मनिपूरी जैसी कई राष्ट्रीयताएं जो अपनी आजादी के लिए लड़ रही हैं, उन्हें

दशकों से भारतीय सेना के जूतों तले कुचला जा रहा है। उन्हें सबसे निर्मम उत्पीड़नों का निशाना बनाया जाता है और सेना को संरक्षण देने वाले कानूनों के जरिए उन्हें सभी तरह के कानूनी प्रतिकार से वंचित रखा जाता है। सेना के सभी तरह के अत्याचारों – हत्याएं, बलात्कार, यातनाएं – को संवैधानिक मंजूरी दी गयी है। अकल्पनीय परिस्थिति में जेलों में बंद हजारों कैदियों की हालत भारतीय लोकतंत्र की इस भयानक तस्वीर को पूरा करता है। इनमें से ज्यादातर बंदी समाज के सबसे निचले पायदान से आते हैं। छोटी-छोटी और मामूली अपराधों के लिए, जिसकी सजा एक या दो सालों से ज्यादा नहीं है, उन्हें वर्षों तक बिना जमानत या मुकदमें के सालों-साल जेल की सलाखों के पीछे रखा जाता है। माओवादी राजनीतिक बन्दियों के मामलों में पुलिस थानों और कैम्पों की यातनाएं जेलों तक जारी रखी जाती है, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं सहित हर तरह के बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता है, साहित्य और अखबार को भी उन तक पहुंचने से रोका जाता है, उनके परिवार के लोगों को उनसे मिलने पर पाबंदियां या पूरी तरह से रोक लगाई जाती है तथा उनके कानूनी अधिकारों का हनन किया जाता है।

हमें इस नरक में क्यों रहना है?

शासक माओवादियों पर हिंसा और विनाश का आरोप लगाते हैं। लेकिन उनके द्वारा संरक्षित इस समाज की हिंसा का क्या? यह समाज व्यवस्था मानव अस्तित्व पर ही क्या निरंतर हमला नहीं है? हर मिनट में अन्त होती अनगिनत जिंदगियों और उन जिंदा लाशों के लिये जो अपने आपको मुश्किल से जिंदा रख पाते हैं, कौन जवाबदेह होंगे? उनके द्वारा समाज और पर्यावरण पर ढायी जा रही कहर और विनाश के लिए कब जिम्मेदार ठहराये जायेंगे? हमारी हिंसा इसी का जायज जवाब है। हम ध्वंस करते हैं इस आदमखोर व्यवस्था को, इसकी मूल्य और संस्कृति को। लेकिन यह कोई विवेकहीन हिंसा नहीं है। देश की व्यापक शोषित जनता के समर्थन और भागीदारी से हमारी पार्टी के नेतृत्व में पीएलजीए विनाश करती है, निर्माण के लिए। यह हिंसा सोची-समझी, उद्देश्यपूर्ण है। पुराने समाज की जमीन को खोदकर यह जनविरोधी और सड़े-गले संबंधों, संरचनाओं और संस्थानों को उखाड़ फेंकती है। जनता के साथ मिलकर यह एक नई राजनीतिक सत्ता और एक नई समाज व्यवस्था की नींव रखती है। क्रान्तिकारी जन कमेटियों (क्रान्तिकारी जनताना सरकार, क्रान्तिकारी जन कमेटी या विप्लव

प्रजा कमेटी आदि के नाम से लोकप्रिय) के रूप में प्राथमिक स्तर पर मध्य और पूर्व भारत के गुरिल्ला आधार इलाकों में ये आज मौजूद है।

नई राजनीतिक सत्ता के ये केन्द्र इस विशाल देश के मानचित्र में कुछ बिंदुएं ही हैं। फिर भी, अभी से ये सहयोग और सामूहिकता के सिद्धान्त और मानवीय मूल्यों से भरी एक अर्थपूर्ण जिंदगी को संभव बना रहे हैं। अपनी जिंदगी का खुद ही मालिक बनने के शोषितों की सदियों पुरानी आकांक्षा को इन्होंने साकार किया। किसानों को जमीन मुहैया करायी। अपनी अलग पहचान को बनाये रखते हुए नये के निर्माण में आदिवासियों की मदद की। दलितों को एक सम्मान की जिंदगी दी। महिलाओं के मुक्ति संघर्ष का समर्थन कर जनसत्ता के इन अंगो ने उन्हें समाज में एक नयी पहचान बनाने में मदद की। यह नई राजनीतिक सत्ता भारत के भविष्य के लोकतांत्रिक, संप्रभुता-सम्पन्न, संघीय, गणराज्य जो कि आत्मनिर्भर, न्यायपूर्ण और समानता पर आधारित हो, का अंकुर है। इसे हकीकत में बदलना संभव है बशर्ते हम लडने की हिम्मत करें और ऊंचाईयों को छूएं।

यह नया समाज क्या है? इसकी उपलब्धियां क्या हैं?

गुरिल्ला आधार इलाकों के इन गांवों में भारतीय राज्य सत्ता को ध्वस्त किया गया है। जनता पर राज करने वाले सामंतवादियों और पारम्परिक आदिवासी नेताओं के पुराने वर्चस्व खत्म हो गया है। जाति के बंधनों को ध्वस्त किया गया है और इसके उन्मूलन के लिए जमीन तैयार की जा रही है। जनता की राजनीतिक सत्ता के अंगों का निर्माण किया गया है। जन युद्ध के जरिए जनता द्वारा हासिल की गई सबसे बड़ी कामयाबी है, यह नयी जनवादी सत्ता। कुछ गिने-चुने जनविरोधियों तथा प्रतिक्रियावादी राज्य और उसके किराये के सशस्त्र बलों व गिरोहों का समर्थन करने वाले तत्वों को छोड़कर सभी वयस्क लोग गांव स्तर की क्रान्तिकारी जन कमेटियों के 9 से 11 सदस्यों का हर तीन सालों में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को 'वापस बुलाने का हक' हासिल है। समान प्रतिनिधित्व के तहत राजनीतिक सत्ता में महिलाओं का समान अधिकार है। जनता को सभी मौलिक जनवादी अधिकार हासिल हैं - जैसे जमा होने का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, हड़ताल और धरना-प्रदर्शन आयोजित करने का अधिकार, अपनी इच्छा के मुताबिक जीवनयापन करने का अधिकार, बुनियादी शिक्षा का अधिकार, बुनियादी स्वास्थ्य

सेवा का अधिकार, न्यूनतम रोजगार का अधिकार, आदि।

जनता के जीवन के हर पहलू पर आरपीसी अपना ध्यान केन्द्रित करती है। इनके सात से नौ विभाग होते हैं।

'जमीन जोतने वालों की' के नारे के तहत उन सभी किसानों को जंगल की जमीन बांटी गयी जिनके पास कोई जमीन नहीं थी या फिर बहुत ही कम जमीन थी। यहां आधी जमीन पर महिलाओं का मालिकाना हक है। ''समान काम के लिए समान मजदूरी'' के नियम को लागू किया जा रहा है। साप्ताहिक बाजारों में असीमित शोषण को रोकने के लिए बाजार कमेटियां कार्यरत हैं। जायज मजदूरी की मांग पर सफल जन संघर्ष लड़े गए हैं और जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए इकठ्टी की जा रही निधी में बढ़ोत्तरी हुई है। वनोपजों के संग्रह पर लगी हर तरह के कर और प्रतिबंध हटाया गया है। वनोपजों का जनता अब मुक्त रूप से संग्रह और उपयोग कर सकती है। ''जंगल पर सभी अधि कार आदिवासियों/स्थानीय जनता को'' के नारे को अमल किया गया है। आरपीसीयों की अनुमति के बिना जंगल से किसी भी तरह के संसाधन को ले जाने पर प्रतिबंध है। साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा दलाल कम्पनियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है।

खेतों की औसतन पैदावार को बढ़ाने के लिए सिंचाई व्यवस्था का निर्माण और उच्च गुणवत्ता वाले स्थानीय बीजों और प्राकृतिक खादों के उपयोग को बढ़ावा देने के अलावा गरीब किसानों को अपनी जमीन जोतने के लिए आरपीसी सभी प्रकार की सहायता मुहैया कराती है। जहां तक परिस्थिति अनुमति देती है, जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए तथा उनकी और पीएलजीए की जरूरतों की पूर्ति के लिए कृषि उत्पाद बढ़ाने की सभी कोशिशें जारी हैं, ताकि बाजार पर निर्भरता कम की जा सके। आरपीसीयां खुद कृषि फर्म स्थापित कर रही हैं। उत्पादन से जुड़े अलग-अलग कामों और सेवाओं के लिए सहयोग/कार्य दलों को गठित किया जा रहा है। सहकारी बीज संगठनों का गठन किया जा रहा है। बगीचों और फल-सब्जियों के पैदावार के जरिए जनता को पौष्टिक आहार मुहैया कराने की कोशिश शुरू की गई है। तालाबों में मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक जिम्मेदारी के रूप में पार्टी और पीएलजीए इन सभी उत्पादन के कामों में अपने श्रम की हिस्सेदारी करती है।

वर्ग संघर्ष के विकास और आरपीसीयों के निर्माण से जनता के संस्कृतिक

जीवन में विकास के नये दरवाजे खुल गये हैं। पारम्परिक आदिवासी नेताओं के लिए किये जाने वाले मुफ्त श्रम का रिवाज बंद होने के साथ-साथ आपसी सहयोग /कार्य दलों के जरिए जनता की अपनी जरूरतों को पूरा करने में बढ़ोत्तरी हुई है। आदिवासी इलाकों में सामूहिक शिकार जो पहले हफ्तों तक चलता था उसे कम किया जा रहा है। इसके बदले श्रमशक्ति को जमीन समतलीकरण और सिंचाई सुविधाएं तैयार करने में लगाया जा रहा है जिससे कृषि उपज में वृद्धि हो रही है।

पारम्परिक रीति-रिवाज, जिनका आंख बंद कर पालन किया जाता था, बदलती परिस्थितियों में उत्पादन शक्तियों के विकास में रूकावट पैदा कर रही हैं। इसलिए, पारम्परिक चिकित्सकों और पूजारियों के साथ सभाएं आयोजित कर चर्चा के बाद इन रीति-रिवाजों में जरूरी बदलाव लाए जा रहे हैं। शादी, त्यौहार और मृत्यु की रीति-रिवाजों में होने वाले फिजूल खर्चे में भी कमी लाई गई हैं।

महिलाओं को अब ज्यादा सम्मान मिलता है। वर्ग संघर्ष के विकास तथा महिला संगठनों के निर्माण के साथ-साथ बलपूर्वक शादियों और गोटूल व्यवस्था (कुछ आदिवासी इलाकों में मौजूद) में काफी कमी आई हैं। महिलाओं और युवतियों को इसने सामाजिक और मानसिक दबाव से मुक्त किया हैं।

जनता की मौलिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पाठशालाएं खोली गई हैं। इतिहास में पहली बार दण्डकारण्य की बहुसंख्यक जनता की मातृभाषा कोया में शिक्षा दी जा रही है। बिहार-झारखंड में भी आदिवासियों, दलितों और शिक्षा से वंचित तबकों को शिक्षित करने की विशेष कोशिश की जा रही है। जनवादी-समाजवादी विचारों की रोशनी में पाठ्यक्रम तैयार किए गए है। जनता की जरूरतों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। गांवों में जनता के डॉक्टरों को प्रशिक्षित कर साफ-सफाई और शुद्ध पेय जल की सुविधा मुहैया कराने का काम सक्रिय रूप से किया जा रहा है। बेघर लोगों के लिए आपसी सहयोग से घर निर्माण किया जा रहा है।

सरकार और वन माफिया के द्वारा जंगलों की बेरोकटोक कटाई तथा मूल्यवान लकड़ी की चोरी को रोक दिया गया है। लोगों की मनमर्जी से कृषि और घरेलू उपयोग के लिए पेड़ों की अव्यवस्थित कटाई के बदले इन्हें आरपीसी द्वारा जनता की जरूरतों के मुताबिक नियंत्रित रूप से उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। मछली और पक्षियों को पकड़ने के लिये जहर के इस्तेमाल पर

पाबंदी लगाई गई है। मांस बेचने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वाणिज्यिक रूप से किए जाने वाले वन्य प्राणियों के शिकार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वन्यप्राणियों के संरक्षण को प्रोत्साहित किया जाता है।

गांव स्तर की आरपीसीयों से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा एरिया स्तर की आरपीसीयों का गठन किया गया है। उसी तरह, एरिया स्तर के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा डिविजनल (जिला स्तर के) आरपीसीयों का गठन करते हैं। यह सांगठनिक विकास जनता की राजनीतिक सत्ता के इलाकेवार विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है जहां जनता नये के निर्माण में जुटे हुए हैं। भारतीय राज्य का सामना करते हुए मुक्तांचल का निर्माण करने की प्रक्रिया को तथा जनता की सरकार स्थापना की तरफ बढ़ते कदमों को आरपीसी मजबूती देती है।

दीर्घकालीन जनयुद्ध की ही ये सभी उपलब्धियां हैं। तीन दशकों से भी ज्यादा समय में अनगिनत कुरबानियों के बदौलत हमारी आन्दोलन ने दण्डकारण्य और बिहार-झारखंड की युद्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। इन दोनों जोनों की अलग-अलग परिस्थितियों के मद्दे-नजर इस प्रक्रिया ने अलग-अलग स्वरूप लिया है, लेकिन दोनों का ही नई जनवादी क्रान्ति की राजनीति ने मार्गदर्शन किया है। बिहार-झारखंड में जाति-सामंतवाद के बंधनों को तोड़ने, उच्च जातियों की निजी सेनाओं का खात्मा करने, जमीन जब्त कर उसे वितरित करने के लिए एक जुझारू हथियारबंद संघर्ष लड़ा गया जिसने नेतृत्वकारी केन्द्र के रूप में क्रान्तिकारी किसान कमेटियों के विकास को सुगम किया। दण्डकारण्य में वन विभाग, निजी ठेकेदारों, सामंतवादी मालिकों और कुछ इलाकों में सामंती पारम्परिक आदिवासी नेताओं के वर्चस्व को ध्वस्त करने के लिये किये गये संघर्षों ने उनके शोषण का अंत करने की जमीन तैयार की, जिनमें हथियारबंद आदिवासी किसान बड़े पैमाने पर भाग लिये। पार्टी और जन संगठनों का निर्माण किया गया। क्रान्तिकारी हथियारबंद बल, जन छापामार सेना और जनमुक्ति छापामार सेना का कदम-दर-कदम निर्माण किया गया। भ्रूण रूप में जन सत्ता का निर्माण हुआ। 2004 में दो क्रान्तिकारी धाराओं के विलय ने इन उपलब्धियों, अनुभवों व सीखों को आन्दोलन में एक शक्तिशाली उछाल के लिये जरूरी आधार में तब्दील किया। परिणाम आपके सामने है।

हमारी पार्टी के नेतृत्व में जनविरोधी परियोजनाओं और राज्य दमन के खिलाफ मजबूत जन संघर्षों का उभरना एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इनमें से,

संघर्ष के नये स्वरूपों को सामने लाने और जनता की व्यापक एकता कायम करने में नंदीग्राम, लालगढ़, नारायणपटना और कलिंगनगर खास तौर पर उल्लेखनीय है। पृथक तेलंगाना राज्य के लिए चले लम्बे संघर्ष की सफलता में हमारी पार्टी के नेतृत्व में क्रान्तिकारी ताकतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पार्टी ने कई अन्य जन संघर्षों का भी मजबूती से समर्थन किया। इससे राज्य दमन का सामना करने तथा उन्हें विभाजित करने की कोशिशों को नाकाम करने में मदद मिली। इन संघर्षों के जरिए जल-जंगल-जमीन पर जनता के अधिकार और इज्जत से जीने के अधिकार को मजबूती मिली।

इस अवसर पर क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रमुख युद्ध क्षेत्रों में जनता की बेमिसाल भूमिका का हमें खास तौर पर उल्लेख करना चाहिए। दमन की क्रूरता का उन्होंने ही सामना किया है। उन्होंने ही हमें साहस और विश्वास दिलाया है। उनकी महान शहादतों और असीमित उत्साह के बिना दीर्घकालीन जनयुद्ध असंभव है। 'पिछड़ों' के रूप में उपेक्षित और अपमानित ये लोग आज मार्गदर्शक और अगुवा की भुमिका में हैं। हम इन्हें - इन इतिहास के निर्माताओं को - एक मिसाल के तौर पर देश के सामने पेश करना चाहते हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं और उन्हें लाल सलाम पेश करते हैं।

भारतीय क्रान्ति की एकमात्र मार्गदर्शक केन्द्र के रूप में भाकपा (माओवादी) के उदय को भारत और दुनिया के पैमाने पर जनता ने स्वागत किया। जबकि जनता इससे प्रेरित हुई, उनके दुश्मन इससे हताश हुए। मौत के कगार पर खड़ी सभी शक्तियों के स्वभाव के अनूरूप अपने बलों को इकट्ठा कर क्रान्तिकारी शक्तियों पर ज्यादा से ज्यादा मारक हमले करने में जुट गए। यह एक चौतरफा हमला था। बर्बर सैनिक बल प्रयोग के साथ ही भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व को निशाना बनाकर उनकी हत्याएं की गयी। शान्ति की झूठी बातों के साथ दुष्प्रचार और सफेद झूठों को फैलाया गया। जनता को जनता के खिलाफ लड़ाने के उद्देश्य से हत्यारे गिरोहों को हथियारबंद किया गया और उन्हें जनता के खिलाफ तैनात किया गया। इसके बावजूद, भारी हमलों का सामना कर और गंभीर नुकसान उठाते हुए पार्टी, पीएलजीए और क्रान्तिकारी जनता संघर्ष में दृढ़ता के साथ खड़ी रही। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जैसे कि बंदी क्रान्तिकारियों को मुक्त करने के लिए किया गया साहसिक जेहानाबाद जेल ब्रेक और पीएलजीए को हथियारबंद करने के लिए ऐतिहासिक नयागढ़ शस्त्रागार पर कब्जा। एकीकृत पार्टी की ऐतिहासिक एकता कांग्रेस - 9वीं कांग्रेस (देश के

स्तर पर पार्टी प्रतिनिधियों की बैठक) सफलतापूर्वक आयोजित की गयी। सैद्धान्तिक, राजनीतिक एकता को और ज्यादा गहरी व मजबूत की गयी। पार्टी की एकताबद्ध सोच को एक ऊंचे स्तर तक पहुंचाया गया। इसकी लड़ाकू क्षमता को तेज किया गया।

भारत के शासक वर्गों ने अपनी प्रतिक्रान्तिकारी योजनाओं में विफल होने के बाद 2009 के मध्यभाग से ग्रीन हंट अभियान शुरू किया और वे उसे दिन-ब-दिन तेज कर रहे हैं। साम्राज्यवाद उनका दिशानिर्देशन कर रहा है, खासकर अमेरिकी साम्रज्यवाद। यह एक खुंखार 'जनता पर युद्ध' है। लेकिन इसका रंग हरा नहीं बल्कि लाल है। यह लाल है, उन आदिवासियों व अन्य जनता के खून से जिन्हें भारतीय राज्य के किराये के बलों ने मार डाला है। यह लाल है जनता की बेटियों और बेटों के खून से जिन्होने निम्न स्तर के हथियारों से लैस होने और संख्या में बहुत ही कम होने के बावजूद आखिरी दम तक बहादुरी से लड़े और अपनी शहादत दी। यह एक 'मैन हंट' हैं। कोवर्टो और 'तृतीय प्रस्तुति कमेटी' जैसी प्रतिक्रान्तिकारी गिराहों द्वारा पार्टी व पीएलजीए सदस्यों को जहर देकर उनकी हत्या की जा रही है। जनता पर हमलों का यह एक उन्मादित बौछार है - पुलिस-अर्द्धसैनिक बल-प्रतिक्रान्तिकारी गिरोहों द्वारा हत्या, बलात्कार, घरों को जलाना, लूटपाट, खेतों और खलिहानों की तबाही, मवेशियों की लूट और हत्या, आदि। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंग में ब्रिटिश औपनिवेशिक दमन की घिनौनी परम्परा को जारी रखते हुए 'कुर्की-जप्ती' प्रावध ान के जरिए अदालतों के निर्देशानुसार माओवादी आन्दोलन से जुड़े लोगों के घर और सम्पत्ति जब्त किए जा रहे हैं। बीजापुर जिले के चिंतलनार इलाके में किया गया हमला, जिसमें चार गांवों को जलाया गया और कईयों की हत्या व बलात्कार की गयी, राज्य दमन का एक घिनौना उदाहरण है। इसी जिले के सरकेगुड़ा में गांववासियों के एक जमावड़े पर गोलीबारी कर महिलाओं और बच्चों सहित 17 लोगों का जनसंहार किया गया। यह इसी हमले का हिस्सा है। जनता को बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं करवाने के कारण के रूप में भारत के शासक वर्ग और उनकी राजनीतिक पार्टियां अकसर धन न होने का बहाना बनाते हैं। लेकिन जनता पर युद्ध में करोड़ों रूपये खर्च करने और इसमे अत्याध ुनिक तकनीकी उपकरण इस्तेमाल करने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती। केन्द्र व राज्य सरकारों के पांच लाख किराये के सैनिकों को पहले ही इस युद्ध में झोंका गया है। पचास हजार अतिरिक्त बल इसमें शामिल हो रहे हैं। वायु सेना

ड्रोन विमान मुहैया करा रही है। वह अब हवाई हमलों की भी तैयारी कर रही है। कमांड और प्रशिक्षण में सेना ब्रीगेड स्तर पर जुटी हुई है। माओवादियों के नेतृत्व में चल रही क्रान्ति के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सेना का एक विशेष बल तैयार करने में तेजी लायी जा रही है।

भारतीय राज्य अपने हमलों में और ज्यादा बेताब और निर्मम हो रहा है। 'जनता पर युद्ध' छेड़ने और 'जनता को जनता के खिलाफ खड़ा करने' के पागलपन के पीछे भी एक तर्क है। दिन-ब-दिन देश की असली हालत उजागर हो रही है। 70 फीसदी जनता महज 20 रूपये प्रति दिन पर अपना गुजर-बसर करने पर मजबूर है और इस परिप्रेक्ष्य में शासकों का यह दावा कि भारत दुनिया के ताकतवर देशों की कतार में शामिल होने जा रहा है, एक भद्दा मजाक के रूप में देखा जा रहा है। इस तंगी और बदहाली के विपरीत मध्य और पूर्वी भारत में खड़ी है, एक नया फौज, एक नई जनान्दोलन, एक नई राजनीतिक सत्ता और एक नया समाज। केवल वंचितों के बीच ही नहीं बल्कि देशभक्तों और प्रगतिशीलों के एक व्यापक तबके को भी यह आकर्षित कर रहा है। साम्राज्यवादियों और भारतीय कम्पनियों द्वारा विकास के नाम पर किये जा रहे मानव और प्राकृतिक संसाधनों के बेतहाशा शोषण, दोहन और लूट के एक असली विकल्प के रूप में इसे देखा जा रहा है। यह एक ऐसी जनवादी नमूना पेश करता है जो शोषित वर्गों, सामाजिक तबकों - मजदूरों, किसानों, शहरी निम्न पूंजीपति, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, राष्ट्रीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों - को साम्राज्यवाद का सामाजिक आधार तैयार करने वाले और दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के साथ सांठगांठ करने वाले ब्राह्मणवादी जातीय-सामंतवाद के वर्चस्व और इससे उपजे सभी प्रतिक्रियावादी मूल्यों से मुक्त करेगा। यह भविष्य की संभवनाओं को दर्शाता है - कैसे भूमिहीन और गरीब किसानों को जमीन मिल सकेगी, सामूहिक श्रम की जबर्दस्त उर्जा को कैसे मुक्त किया जा सकेगा, कैसे पारम्परिक ज्ञान को नये की सेवा में उपयोग किया जाएगा, कैसे जनता के हितों को केन्द्र में रखते हुए सही विकास और पर्यावरण के संरक्षण को संभव बनाया जाएगा। एक नये भारत के निर्माण की असीमित संभवनाओं को यह भ्रूण रूप में दर्शाता है। एक ऐसा भारत जो मौजूदा भारत राज्य के विनाश के बाद इसकी राख से ही पैदा हो सकता है। हां, भारतीय शासकों की बेचैनी के ठोस कारण मौजूद हैं। इस नयी सत्ता और समाज का अस्तित्व हर दिन उनके शरीर पर वार करती है। इसमें उन्हें अपना अंत दिखाई देता है। इसलिए इसे ध्वस्त

करने के लिए वे बेताब है।

इसके अलावा, इन इलाकों के संसाधनों को देशी और विदेशी कम्पनियों के हाथों बेचने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें पहले ही बड़ी संख्या में करारनामे कर चुकी हैं। लेकिन जनता की हिस्सेदारी से जनता की सरकारों का विकास और विस्तार तथा जल-जंगल-जमीन पर जनता की राज सत्ता कायम होने से उनकी योजनाएं विफल हो गई है। उन्हे लागू करने के लिये अब वे काफी दबाव में है। साम्राज्यवादी व्यवस्था आज विश्वव्यापी आर्थिक संकट की गिरफ्त में है। भारत की अर्थ व्यवस्था को यह बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। जनता के दुश्मन ये साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और उनके भारतीय दलाल इस संकटकालीन परिस्थिति में हमारे देश के संसाधनों की बेतहाशा लूट और मेहनतकश वर्गों के बेलगाम शोषण के लिए बेताब है। यही कारण है संघर्षरत जनता को कुचलने में की जा रही जल्दबाजी का, चाहे इसके लिए जितना भी खून बहाना पड़े।

भाड़े के सरकारी बलों के पैरों तले जनता को कुचला जा रहा है। वे उन्हें मारपीट करते और गोली मारते हैं। लेकिन यही सब कुछ नहीं। वे 'उपहारों' के साथ भी आते हैं। शिक्षा से वंचित आदिवासी बच्चों पर वे सभी तरह के उपकरणों की बौछार करते हैं, कपड़े बांटते हैं और खाना परोसते हैं व उन्हें रहने और पढ़ने की सुविधा देने का दावा करते हैं। अंदरूनी गांवों से वे उन्हें ''भारत भ्रमण'' पर ले जाते हैं। सैनिक जूतों और संगीनों का साथ देता यह 'मुलायम स्पर्ष' का तरीका है। जनता में से एक हिस्से को लुभाकर मुखबिर नेटवर्क का आधार तैयार करने के अमेरिकी साम्राज्यवाद और उसके गुर्गों की यह एक शातिराना साजिश है। वे सुधार और विकास के वादों के साथ आते हैं, लेकिन उद्देश्य केवल जनता को विभाजित करना है। इसका लक्ष्य है, माओवादियों को अलग-थलग करना व क्रान्तिकारी आन्दोलन पर दमन तेज करना, नयी राजनीतिक सत्ता को ध्वस्त करना और जनयुद्ध के विस्तार को रोकना। ये उद्देश्य पूरा होने के बाद सब कुछ फिर से पहले के जैसा ही चलने लगेगा - जनता की बुनियादी अधिकारों व सुविधाओं से वंचित करना और उनके संसाधनों की नीलामी करना। इसके प्रमाण के रूप में आप झारखंड के सरांडा को ही ले सकते हैं। पहले, क्रान्तिकारी संगठनों को नष्ट करने और पीएलजीए को निकाल बाहर करने के लिए दस हजार बलों के साथ एक आकस्मिक और

चौरतफा निर्मम आक्रमण किया गया। उसके बाद, सभी के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के वादों के साथ विशेष सरांडा विकास प्राधिकरण की स्थापना। और अंत में असली चीज – लौह अयस्क के खनन के लिए हजारों हेक्टेयर घने जंगल टाटा के हवाले करना; संसाधनों से धनी इस इलाके में सौ से भी ज्यादा साम्राज्यवादी और दलाल कम्पनियों का आगमन तथा पुलिस थानों और नौकरशाहों–स्थानीय शोषकों के घृणित राज की वापसी। भारत राज्य द्वारा चलाए जा रहे प्रतिक्रान्तिकारी अभियानों का यही असली मकसद है।

भारत में सशस्त्र क्रान्ति सशस्त्र प्रतिक्रान्ति का सामना कर रही है। भारतीय राज्य के बेहतर रूप से सज्जित बलों के विरूद्ध जनयुद्ध की छापामार कार्यनीतियों का प्रयोग कर पीएलजीए दुश्मन पर पलटवार कर रही है। दुश्मन के बलों के चरित्र के विपरीत, इसकी शक्ति छुपी है, जनता के साथ इसके गहरे संबंध में, इसकी सृजनशीलता और फौलादी दृढ़संकल्प में। मुकरम (दण्डकारण्य) में पीएलजीए द्वारा सीआरपीएफ की एक पूरी कम्पनी का सफाया राज्य के 'जनता पर युद्ध' का मुंहतोड़ जवाब था। दीर्घकालीन जनयुद्ध में, भूभाग पर नियंत्रण के बजाए क्रान्तिकारी सैन्य बल का संरक्षण निर्णायक होता है। इस सिद्धान्त को आत्मसात करते हुए भारतीय राज्य के उन सभी प्रयासों से पीएलजीए बच निकलती है जिनमें वे इसे एक ही जगह पर सीमित रखकर ध्वस्त करने की कोशिश करता है। दुश्मन के छोटी टुकड़ियों पर हमला कर वह उनकी घेराबंदी तोड़कर बाहर आती है। दुश्मन के बहुत बड़े सैन्य बलों का सामना होने पर पीछे हटकर उनके चारों ओर चक्कर काटते हुए मौका मिलने पर पीएलजीए उस पर वार करती है। तोंगपाल एम्बुश (दण्डकारण्य) जिसमें 15 भाड़े के जवानों का सफाया किया गया व 20 हथियार और बड़े पैमाने पर गोलीबारूद जब्त किए गए तथा फरसागांव (झारखंड) एम्बुश जिसमें पांच दुश्मन के सैनिकों का खात्मा किया गया और पांच हथियार बरामद किए गए, जनयुद्ध की ताकत का परिचय देते हैं। यह एक ऐसा युद्ध है जिसका माओवादी पार्टी नेतृत्व करती है और जनता को हजारों की संख्या में इसमें शामिल करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एम्बुश ऐसी जगहों पर की गई जिन्हें भारतीय राज्य माओवादियों से 'मुक्त' करने का दंभ भरता था। इस साल जनवरी से जून के बीच नौ राज्यों में दुश्मन द्वारा दो देशव्यापी दमन मुहिम चलाये गये – पहला दिसम्बर–जनवरी 2013–2014 के दरम्यान और दूसरा मार्च 2014 में। इस अवधि में पीएलजीए ने 39 कार्रवाईयों को अंजाम दिया।

नई राजनीतिक सत्ता, नये आन्दोलन, नई राजनीतिक शक्ति और नये समाज के खिलाफ भारतीय राज्य के आक्रमण का प्रतिरोध करना केवल पीएलजीए का ही मुद्दा नहीं है। जनता इसमें मजबूती के साथ शामिल है। कार्रवाईयों की तैयारी और कार्यान्वयन में जनता भाग लेती है; खाना, आश्रय और सूचना देती है, आपूर्ति में मदद करती है और दुश्मन के साथ सहयोग करने से इन्कार करती है। पीएलजीए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है मिलिशिया। कार्रवाईयों में इसकी भूमिका के अलावा सलवा जुडूम, सेन्द्रा और अन्य प्रतिक्रान्तिकारी हत्यारे गिरोहों के हमलों को नाकाम करने व उन्हें ध्वस्त करने में इसने एक विशेष भूमिका निभाई। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें जनता ने दमन का वीरता से सामना कर शहीदों की लाशों को दुश्मन के कब्जे से वापस लायी और उन्हें उपयुक्त अंतिम श्रद्धांजली अर्पित की। कुछ अन्य मौकों पर उन्होंने दुश्मन बलों द्वारा वितरित सामानों को आग के हवाले कर दिया। मिनपा में जनता ने पीएलजीए के साथ मिलकर एक हफ्ते तक लगातार संघर्ष कर दुश्मन को उनके कैम्प को बंद करके भागने पर मजबूर कर दिया। हर्राकोडेर में आस-पास के गावों से जनता जमा होकर शांतिपूर्ण, लेकिन दृढ़, प्रतिरोध कार्यक्रम के जरिए अर्धसैनिक बलों के एक नये केम्प को वापस लेने के लिए मजबूर किया। महिलाओं ने अपनी भूमिका से इसमें एक मिसाल कायम की। देश और विदेश के बुद्धिजीवियों, प्रगतिशीलों और जनवादियों का एक तबका भारतीय राज्य के 'जनता पर युद्ध' का विरोध करने व इसके अत्याचारों को बेनकाब करने बड़ी संख्या में सामने आये।

प्यारी जनता,

हमारी आजीविका, इज्जत और अस्तित्व विदेशी और भारतीय कम्पनियों के शोषण को तेज करने वाली नई-उदारवादी नीतियों के चौतरफा हमलों का सामना कर रही हैं। बड़ी परियोजनाओं, खदानों, विद्युत संयत्रों, बांध, बंदरगाह, हवाई अड्डा, सुपर-हाईवे, मेट्रो रेल, हाई-टेक शहर, पर्यटन केन्द्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र आदि के नाम पर हमारे लाखों लोगों को बेघर किया जा रहा है। शासकों की विनाशकारी नीतियां प्राकृतिक आपदाओं को जन्म दे रही हैं जो सैकड़ों लोगों की जानें ले रही हैं और हजारों को बेघर व बेसहारा बना रही हैं। मजदूरों के संघर्षों से हासिल अधिकारों पर लगाम लगाने के लिए वे एक के बाद एक नये कानून ला रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था का ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों का नियंत्रण

वे साम्राज्यवादी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंप रहे हैं। विदेशी पूंजी और हाईब्रीड बीज जैसे तकनीकों की घुसपैठ के लिए कृषि क्षेत्र को तैयार किया जा रहा है। रीयल इस्टेट 'भूमि बैंकों' के नाम पर और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के नये रूपों में भूमि का केन्द्रीकरण हो रहा है। कार्पोरेट फार्मिंग (बाजार के लिए खेती) को बढ़ावा दिया जा रहा है। मौजूदा कानूनों में बदलाव लाये जा रहे हैं ताकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मालिकों के खिलाफ देश में मुकद्दमा न चलाया जा सकें, चाहे उनका जो भी गुनाह हों।

इनकी परियोजनाओं के लिए वे जमीन हड़प रहे हैं, जबकि किसानों के वंचित तबकों की जमीन की मांग को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बड़े जमींदारों का अभी भी इस बहुमूल्य संसाधन पर एकाधिकार है। वे रासायनिक खाद और अन्य आधुनिक कृषि उपकरणों की बिक्री और कृषि उत्पादों की खरीद्दारी जैसे व्यापारों में भी जुट गए हैं। वे या तो प्रत्यक्ष रूप से सूदखोरी का काम करते हैं या फिर सहकारी सोसाइटी का नियंत्रण करते हैं। वे ही शासक वर्गों के राजनीतिक पार्टियों के विधायक, सांसद और मंत्री बनते हैं, स्थानीय निकायों को नियंत्रित करते हैं और पुलिस बलों पर अपना प्रभाव बरकरार रखते हैं। इस तरह वे दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों के साथ मिलकर किसानों और देहाती गरीबों पर सम्पूर्ण नियंत्रण कायम करते हैं और देश की प्रगति के पथ पर एक बड़ी बाधा बन कर मौजूद रहते हैं।

जहां भी जनता विरोध करती है उन्हें बर्बर हिंसा और फासीवादी कानूनों का सामना करना पड़ता है। चुनावों के जरिए लोकतंत्र का ढोंग रचा जाता है, जबकि देश की जमीनी सच्चाई है, बढ़ता फासीवादीकरण। फासीवादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक हथियार हत्यारा मोदी को प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बिठाकर, शासक वर्गों और उनके साम्राज्यवादी आकाओं द्वारा ब्राह्मणवादी हिन्दू फासीवाद को जान-बूझकर बढ़ावा दिया जा रहा है। बेहद प्रतिक्रियावादी धार्मिक कट्टरपंथ को उकसाकर साम्प्रदायिक हिंसा फैलाया जा रहा है, जिसमें खासकर मुसलमान अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। देश की दयनीय पराधीनता को छुपाने के लिए संकीर्ण अंध-राष्ट्रवाद को हवा देकर भारत को एक विश्व-शक्ति बनाने के झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। 'हिन्दी-हिन्दू' की अवधारणा को थोपने की शातिराना कदमों के जरिए राष्ट्रीयताओं के संस्कृतियों और धार्मिक भिन्नताओं, यहां तक कि देश के औपचारिक संघीय ढांचे को भी, मिट्टी में मिलाया जा रहा है।

शासकों को अच्छी तरह मालूम है कि जनता का आक्रोश चरम पर है। उनकी सभी राजनीतिक पार्टियां अतीत में केन्द्र या राज्य स्तर पर सरकार में रही हैं या वर्तमान में सत्तासीन हैं। जनविरोधी, भ्रष्ट और देशद्रोही ताकतों के रूप में इन सभी पार्टियों की पहचान हो चुकी है व इनका पर्दाफाश हो चुका है। समय-समय पर वे अलग-अलग किस्म के सुधार कार्यक्रम लाते रहते हैं। इन झूठे सुधारों के जरिए वे जनता को शांत और निष्क्रिय रखना चाहते हैं, ताकि वे अपने शोषण और उत्पीड़न को और भी ज्यादा तेज कर सकें। इस तरह, भूमंडलीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के रूप में साम्रज्यवाद की भयावह घुसपैठ को ''एक मानवीय चेहरे के साथ भूमंडलीकरण'' के बतौर पेश किया जा रहा है। जी हां, वे मुस्कुराते हुए आपको आपके घर से बाहर ढकेल सकते हैं, या आपको आपकी नौकरी से निकाल सकते हैं या आपके पुरखों की जमीन पर ही आपको जिंदा गाढ़ सकते हैं। उनकी 'जनता पर युद्ध' का ऐसी ही कार्यनीति है। पहले तो वे आपको प्रताड़ित करते हैं और बाद में आपको ही उपहार भेंट करते हैं!

प्यारे लोगों,

हमारे देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। सवाल है, हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? आगे की तरफ - देश के चारों दिशाओं में जनयुद्ध की आग को फैलाकर असली आजादी हासिल करने के लिए? या पीछे की तरफ - और ज्यादा बदहाली, और ज्यादा पराधीनता, और ज्यादा बर्बादी के लिये? हम आपके निर्णय का इंतजार करेंगे। हमें विश्वास है कि हमारी लड़ाई में ही आप अपना भविष्य देखते हैं। बहरहाल, भारतीय राज्य और उसके विदेशी आकाओं के खिलाफ अपने आपको झोंककर और अपना सबकुछ दाव पर लगाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पीठ पर सवार तीन पहाड़ों को ध्वस्त करने के महान लक्ष्य से ऐतिहासिक नक्सलबाड़ी सशस्त्र किसान आन्दोलन से शुरू होकर आज तक बारह हजार से ज्यादा साथियों ने अपनी शहादत दी। हम यह भी जानते हैं कि इस लड़ाई के क्रम में कई और साथियों को भी यह सर्वोच्च बलिदान देना होगा। जनता की सेवा में और देश को आजाद करने के लिए हम कम्युनिस्ट किसी भी तरह की शहादत से नहीं हिचकिचाते। हम आगे बढ़ते जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं उस नई सुबह को लाने के लिए जब देश के दुश्मनों का अंततः खात्मा होगा, जब साम्राज्यवादियों को मार भगाया जाएगा और जब हम एक आत्मनिर्भर

भविष्य का निर्माण शुरू कर सकेंगे तथा अपने देश के और अलग-अलग राष्ट्रीयताओं तथा लोगों के सर्वांगीन और समानता पर आधारित विकास सुनिश्चित कर सकेंगे। आईए, हमारी महान पार्टी की स्थापना की दसवी वर्षगांठ समारोह को हम हर गुरिल्ला इलाकों और लाल प्रतिरोघ इलाकों में, गावों और शहरों में, देश और विदेश में क्रान्तिकारी हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाएं, जनयुद्ध की संदेश को जन-जन तक पहुँचाएं और क्रान्तिकारी आन्दोलन को दोगुणे दृढ़संकल्प के साथ आगे बढ़ाएं।

*** भाकपा (माओवादी) की दसवी वर्षगांठ को क्रान्तिकारी उत्साह के साथ मनाएं!**

*** एक नये जनवादी भारत के निर्माण की महान संघर्ष में हमारा साथ दें!**

*** भाकपा (माओवादी) और पीएलजीए में शामिल हों, ये आपकी हैं!**

*** भारत के जनयुद्ध को विस्तारित करें और आगे बढ़ाएं!**

*** सशस्त्र कृषि क्रान्ति की लाल आग को फैला दें!**

*** भारतीय राज्य के 'जनता पर युद्ध' - आपरेशन ग्रीन हंट का विरोध करें, प्रतिरोध करें और इसे ध्वस्त करें!**

*** संगठित हो, करोड़ों की तादाद में उठ खड़े हों और भारतीय राज्य के जनविरोधी, देश को बेचने वाली नीतियों का मुंहतोड़ जबाव दें!**

*** ब्राह्मणवादी हिन्दू फासीवादी मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष में एकजुट हों!**

*** संघर्ष की हिम्मत करें! जीत की हिम्मत करें!**

*** भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेने की हिम्मत करें!**

Økfrdkjh vfHkoknu ds lkFk

केन्द्रीय कमेटी

1 fl rEcj 2014 **भाकपा (माओवादी)**